

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 365/2014/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवचन, घट प्रथम, वृत-द्वितीय, जयपुर
बनाम

अपीलार्थी

मैसर्स समृद्धि ऑयल प्रोडक्ट प्रा.लि.
जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री आर. के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।

निर्णय दिनांक: 17.05.2017

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, घट प्रथम, वृत-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 253/अपील्स/जयपुर/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 20,301/-को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.09.1998 को वाहन संख्या एमपी-36/टी-9494 को अजमेर-जयपुर रो पर जांच हेतु रोका गया। वाहन चालक ने वाहन में लदे माल के समर्थन में बिल नम्बर 4 दिनांक 22.09.1998 तथा Way Bill from no. 3760871 प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मैसर्स काकर्तिकेय कारपोरेशन ने उक्त व्यवहारी को आदेशानुसार अपनी आढत में 67 बोरी तिल खरीदकर भिजवाया था तथा माल की कुल लागत रु. 1,21,505/-थी। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि मैसर्स समृद्धि ऑयल प्रोडक्ट प्रा.लि. का ही माल था जो उन्हें स्टॉक ट्रांसफर के रूप में परिवहनित किया जा रहा था। स्टॉक ट्रांसफर के रूप में परिवहनित किये जा रहे माल के साथ वक्त चेकिंग दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए संलग्न नहीं था, जिसका संलग्न होना आवश्यक है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (2) सपठित नियम 53 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र 18ए पूर्ण रूप से भरा हुआ पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत घोषणा पत्र को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए एवं जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत करने

को बाद की सोच मानते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत माल की कीमत रू. 101505/- पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 20301/- आरोपित कर आदेश दिनांक 07.10.1998 पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2013 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित किया जा रहा माल स्टॉक ट्रांसफर पर जा रहा था, जिसके साथ अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषणा पत्र एस टी 18ए होना आज्ञापक है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए नहीं होने कारण अधिनियम की धारा 78(2)(ए) उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति रू. 20,301/- आरोपित की, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2013 पारित किया है, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

बावजूद सूचना के प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 29.09.1998 को वाहन संख्या एमपी-36/टी-9494 को अजमेर-जयपुर रो पर जांच हेतु रोका गया। वाहन चालक ने वाहन में लदे माल के समर्थन में बिल नम्बर 4 दिनांक 22.09.1998 तथा Way Bill from no. 3760871 प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मैसर्स कार्तिकेय कारपोरेशन ने उक्त व्यवहारी को आदेशानुसार अपनी आढत में 67 बोरी तिल खरीदकर भिजवाया था तथा माल की कुल लागम रू. 1,21,505/- थी। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि मैसर्स समृद्धि ऑयल प्रोडक्ट प्रा.लि. का ही माल था जो उन्हें स्टॉक ट्रांसफर के रूप में परिवहनित किया जा रहा था। स्टॉक ट्रांसफर के रूप में परिवहनित किये जा रहे माल के साथ वक्त चेकिंग दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए संलग्न नहीं था, जिसका संलग्न होना आवश्यक है। अतः कर निर्धारण

अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (2) सपठित नियम 53 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि वक्त चेकिंग पाया गया माल स्टॉक ट्रांसफर के रूप में परिवहनित किया जा रहा था, जिसके साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए होना आवश्यक था, जो परिवहनित माल के साथ नहीं था, किन्तु नोटिस के जवाब में घोषणा पत्र 18ए नहीं होने के तथ्यों को उजागर करते हुए घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 20589 प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वक्त जांच दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र 18 ए नहीं होना सद्भाविक (**bonafide**) भूल है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स डी पी मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

उक्त सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट-2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश को उद्धृत किया जाना समीचीन है :-

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता बांसवाडा के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-


"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2013 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य